project have been selected and advance order has been placed.

(b) Installation work has not yet been started.

Fire in Czech Airliner

*468. **Shri Basumatari:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Ram Harkh Yadav:

Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Czechoslovak Airlines Jet liner, TU-104, caught fire at Santa Cruz airport on the evening of 16th August, 1963;

(b) whether an inquiry was ordered; and

(c) if so, the findings thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a). Yes, Sir.

(b) and (c): A Committee of Inquiry has been appointed by Government under Rule 74 of Indian Aircraft Rules to investigate the incident. Its report is awaited.

कपास

*४६६. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में अब तक कपास का उत्पादन आशानुकूल नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण यह है कि कपास की फसल वर्षा पर निर्भर रहती है और सिंचित कपास का क्षेत्र केवल १३ प्रतिशत रहा है ।

(ग) देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(१) एक ऐसी समाकलित कपास विकास योजना चालू की गई है जिस पर २१६ लाख रुपए खर्च आयेंगे ।

(२) इसके अतिरिक्त कपास की खेती को तेजी से बढ़ाने के लिए २·५४ लाख एकड़ के क्षेत्र में पैकेज प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है । इस काम के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगा दिया गया है जिसका खर्चा केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें बराबर बराबर उठायेंगी ।

(३) पैकेज प्रोग्राम को लम्बी और मध्य की रेशेदार कपास के सिंचे हुये कुल १६·७ लाख एकड़ क्षेत्र में बढ़ाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(४) भारत सरकार बीज, उर्वरक और पौद सरक्षण के सामान खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण और इन मदों के लिए आर्थिक सहायता देने की भी सुविधाय बढ़ा रही है ।

(५) १९६३–६४ में हवाई छिड़काव की विशेष सुविधा को बढ़ा दिया गया है सरकारी जहाजों का प्रयोग करने पर नाममात्र एक रुपया प्रति एकड़ वसूल किया जाता है । गैर सरकारी जहाजों के प्रयोग किए जाने पर परिचालन-लागत का दो-तिहाई हिस्सा ही केन्द्रीय सरकार सहन करती है ।